(ङ) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनी राष्ट्रीय स्तर की उपर्युक्त संस्था की सहायता से कोई श्रम कल्याण योजना तैयार की है?

श्रम मंत्री (श्री पी॰ एम॰ संगमा): (क) और (ख) सरकार ने कोई राष्ट्रीय श्रम केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(ग) और (घ) अधिकतर श्रम कानून संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मकारों पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने असंगठित कर्मकारों की कुछ श्रेणियों के लिए उन्हें स्वास्थ्य, आवासीय, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक और आमोद-प्रमोद सुविधाएं प्रदान करने के लिए कल्याण निधियां स्थापित की हैं।

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

67. **श्री नरेश यादव**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार, देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गोदामों की संख्या, राज्यों की मांग के अनुसार पर्याप्त है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में ऐसे गोदाम जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं जिसके कारण बहुमूल्य खाद्यान्नों का भण्डारण अत्यन्त कठिन हो गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1.6.1995 को स्थिति के अनुसार अपने और किराये के विभिन्न प्रकार के गोदामों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) माइक्रो स्तर पर निगम द्वारा निर्मित/किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या वर्तमान स्टाक का भण्डार करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। तथापि, पिछड़े, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों तथा अधिक वसूली क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम की आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.60 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गोदामों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के फील्ड इंजीनियरिंग कार्मिकों द्वारा नियमित आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। जहां कहीं आवश्यक हो वहां समय पर मरम्मत और रख-रखाव कर गोदामों को भण्डारण योग्य रखा जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1.6.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न प्रकार के गोदामों (निजी और किराये के दोनों) के राज्यवार ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गोदामों की कुल संख्या
1.	बिहार	66
2.	उड़ीसा	46
3.	पश्चिम बंगाल	79
4.	सिक्किम	3
5.	असम	43
6.	अरूणाचल प्रदेश	3
7.	त्रिपुरा	7
8.	मणिपुर	3
9.	नागालैंड	5
10.	मिजोरम	5
11.	मेघालय	6
12.	दिल्ली	10
13.	हरियाणा	142
14.	हिमाचल प्रदेश	17
15.	जम्मू तथा कश्मीर	16
16.	पंजाब	544
17.	चण्डीगढ़	17
18.	राजस्थान	125
19.	उत्तर प्रदेश	292
20.	आन्ध्र प्रदेश	172
21.	केरल	32
22.	कर्नाटक	40
23.	तमिलनाडु	32
24.	गोवा	3
25.	गुजरात	58

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गोदामों की कुल संख्या
26.	महाराष्ट्र	67
27.	गोवा	1
28.	मध्य प्रदेश	177
	जोड़:	2008

Warehouses for Foodgrains

68. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what are the names of the varieties of foodgrains in respect of which arrangement exists for their storage in foodgrains warehouses of the country;

(b) what is the quantum of food items stored at present in the food warehouses of the country; and

(c) whether any time schedule is fixed for keeping different types of foodgrains in the foodgrain warehouses?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Food Corporation of India makes arrangements mainly for the storage of wheat, rice & paddy.

(b) There was 236.1 lakh tonnes of foodgrain stock lying in Food Corporation of India godowns as on 1.6.95.

(c) No, Sir. No time schedule is fixed for keeping different types of foodgrains in the godowns. At the time of issue, the priority is given to foodgrains which are received first. Foodgrains are stored in Godowns/Warehouses till the quality of the same conforms to the P.F.A. (Prevention of Food Adulteration Act) standards.

Balance of Trade between Malaysia and India

69. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the balance of trade between Malaysia and India;

(b) what were the major products exported to Malaysia by India and its value during 1993-1994 and 1994-1995;

(c) what were the major products imported from Malaysia during 1993-94 and 1994-95 and its value; and

(d) whether an Indo-Malaysia Joint Commission has been set up, if not, whether there is any proposal to set up such a Commission?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) During 1994-95 the balance of trade was in Malaysia's favour to the tune of Rs. 633.61 crore.

(Value in Rs. crore)

Major products exported to Malaysia

		1993-94	1994-95
1.	Meat & preparations	117.29	149.85
2.	Cotton yarn, fabrics & made-ups.	47.82	87.54
3.	Machinery & instruments	114.48	69.05
4.	Manufacture of metals	58.59	62.20
5.	Oilmeals	118.10	58.71
6.	Transport equipment	40.40	53.32
7.	Fruits & vegetables	34.30	52.17